PCSMANTRA.IN | हिंदी करेंट अफेयर्स

कैबिनेट के चार बड़े फैसले: कामराजार टर्मिनल, सिलचर एयरपोर्ट और भारत पोस्ट का नया रूप

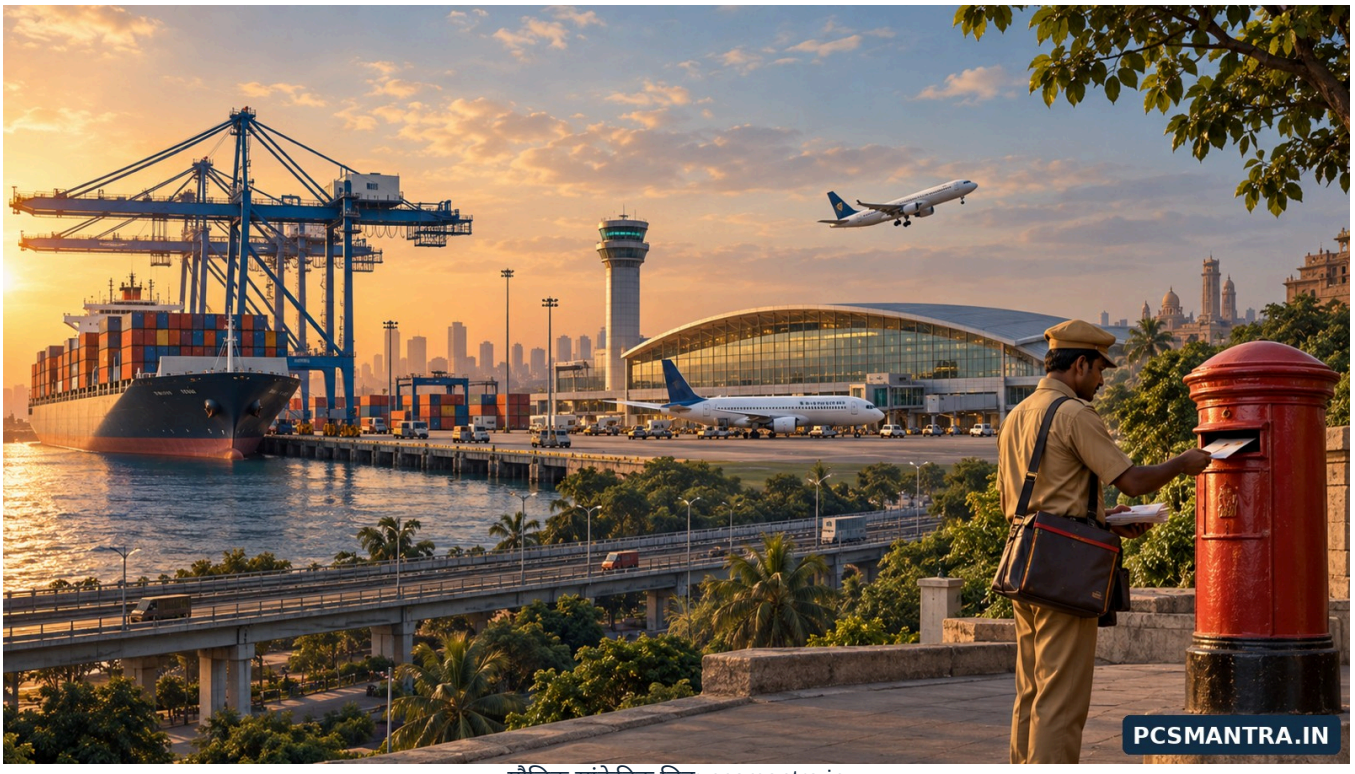

मौलिक सांकेतिक चित्र: pcsmantra.in

समाचार-संदर्भ: 25 नवंबर 2026 (केंद्रीय मंत्रिमंडल व CCEA की बैठकें) और 26 नवंबर 2026 (संचार मंत्रालय की ब्रीफिंग)
मुख्य परीक्षा: GS-III — भारतीय अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, निवेश मॉडल
प्रिलिम्स: आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचा, सरकारी योजनाएँ, बंदरगाह और डाक सेवाएँ

खबरों में क्यों

25 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठकों में पाँच बड़े आर्थिक निर्णय लिए गए, जिनका कुल वित्तीय परिमाण **₹19,934 करोड़** है। इनमें निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण (CIE) विनिर्माण योजना, कामराजार पोर्ट का दूसरा कंटेनर टर्मिनल, सिलचर (डोलू) में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और डाक विभाग की दो योजनाएँ शामिल हैं। CIE योजना पर हम पहले ही विस्तृत लेख प्रकाशित कर चुके हैं; इस लेख में बाकी चार फैसलों की पूरी जानकारी है।

> **पढ़ें:** CIE विनिर्माण योजना: ₹11,000 करोड़ की मंज़ूरी — टनल बोरिंग मशीन जैसे उन्नत उपकरणों के घरेलू उत्पादन के लिए बिक्री-आधारित प्रोत्साहन योजना।

क्या-क्या मंज़ूर हुआ

निर्णय	राशि (₹ करोड़)	मंज़ूरी देने वाली संस्था
CIE विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र योजना	11,000	केंद्रीय मंत्रिमंडल
कामराजार पोर्ट का दूसरा कंटेनर टर्मिनल	4,288.26	CCEA
सिलचर (डोलू) ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट	2,014	CCEA
डाक संचालन योजना	1,141	केंद्रीय मंत्रिमंडल
एस्टेट्स प्रबंधन योजना (डाक विभाग)	1,491	केंद्रीय मंत्रिमंडल
कुल	**19,934**	

कामराजार पोर्ट का दूसरा कंटेनर टर्मिनल

परियोजना का स्वरूप: तमिलनाडु के कामराजार पोर्ट लिमिटेड (KPL) पर दूसरा कंटेनर टर्मिनल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में DBFOT यानी 'डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर' आधार पर बनेगा। इस मॉडल में निजी रियायतग्राही (कंसेशनर) परियोजना डिज़ाइन करता है, पैसा लगाता है, बनाता और चलाता है, और रियायत अवधि पूरी होने पर संपत्ति सरकार को सौंप देता है। रियायत अवधि **40 वर्ष** (48 माह के निर्माण काल सहित) होगी।

लागत और पैसा किसका: परियोजना की अनुमानित लागत **₹4,288.26 करोड़** (GST सहित) है — चरण-1 के लिए ₹2,429.32 करोड़ और चरण-2 के लिए ₹1,858.94 करोड़। यह पूरा निवेश चयनित निजी कंसेशनर करेगा; **भारत सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं** पड़ेगा। इसके अलावा KPL स्वयं ड्रेजिंग (बंदरगाह के जलमार्ग की गहराई बनाए रखने का कार्य) पर अलग से लगभग **₹450 करोड़** खर्च करेगा। यह ड्रेजिंग राशि परियोजना लागत से अलग है।

क्षमता और आकार: 900 मीटर लंबा टर्मिनल, 30 मीटर चौड़ा बर्थ, 18 मीटर ड्राफ्ट (जहाज़ के डूबने की गहराई) और 2.0 मिलियन TEU की वार्षिक क्षमता। TEU यानी 'ट्वेंटी-फुट समतुल्य इकाई' कंटेनर मापने की मानक इकाई है। पहले चरण में 1.1 मिलियन और दूसरे चरण में 0.9 मिलियन TEU की क्षमता बनेगी। टर्मिनल 24,346 TEU और 400 मीटर लंबाई तक के जहाज़ संभाल सकेगा।

समय-सीमा: चरण-1 रियायत प्रदान करने की तिथि से 24 माह में पूरा होगा और 25वें माह से व्यावसायिक संचालन शुरू होगा; चरण-2 का निर्माण 25वें से 48वें माह तक चलेगा और 49वें माह से पूर्ण संचालन शुरू होगा।

क्यों ज़रूरी: भारत के बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 25.7 मिलियन TEU संभाले, जो 2019-20 में 17.2 मिलियन थे। KPL का कंटेनर ट्रैफ़िक सालाना 9-11% बढ़ रहा है और 2034 तक 2.45 मिलियन TEU पहुँचने का अनुमान है, जबकि मौजूदा क्षमता 1.4 मिलियन TEU है। मौजूदा टर्मिनल की स्थापित क्षमता 0.8 मिलियन TEU है और वित्त वर्ष 2025-26 में इसका उपयोग लगभग 88% रहा। नया टर्मिनल विदेशी गहराए हब बंदरगाहों (जैसे ट्रांसशिपमेंट केंद्रों, जहाँ माल एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में बदला जाता है) पर निर्भरता घटाएगा।

KPL की ताज़ा स्थिति: वित्त वर्ष 2025-26 में KPL ने 49.08 मिलियन टन कार्गो और 1,008 जहाज़ संभाले, जिनमें 7 लाख से अधिक TEU कंटेनर शामिल थे। पोर्ट का राजस्व लगभग ₹1,280 करोड़ और कर-पूर्व लाभ ₹924 करोड़ रहा। KPL देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और पूरी तरह चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी का स्वामित्व है; इसका पुराना नाम एनोर पोर्ट है। परियोजना से निर्माण अवधि में लगभग 750 और संचालन चरण में लगभग 800 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलने का अनुमान है।

सिलचर (डोलू) ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

क्या मंज़ूर हुआ: CCEA ने असम के कछार ज़िले के डोलू में **₹2,014 करोड़** की लागत से नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंज़ूरी दी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अर्थ है बिल्कुल नई जगह पर शून्य से बनाया जाने वाला हवाई अड्डा। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) बनाएगा और **पूरा वित्तपोषण AAI के अपने आंतरिक संसाधनों** से होगा, केंद्रीय बजट से नहीं।

मौजूदा हवाई अड्डे की सीमा: अभी सिलचर का हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है, जिसमें AAI सिर्फ 70 एकड़ के नागरिक एन्क्लेव से संचालन करता है। यह A320/B737-800 तक के विमानों के लिए ही उपयुक्त है, यात्री संख्या क्षमता से अधिक हो चुकी है और विस्तार के लिए ज़मीन भी नहीं है।

नए एयरपोर्ट की विशेषताएँ: 12,351 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन, पीक आवर में 800 यात्री (400 आगमन + 400 प्रस्थान) और वार्षिक लगभग 1.01 मिलियन यात्रियों की क्षमता; 2,705 मीटर × 45 मीटर का Code-4C रनवे (A-320 संचालन हेतु); 6 विमानों की पार्किंग वाला नया एप्रन और अलग आइसोलेशन बे।

महत्व: डोलू बराक घाटी का रणनीतिक केंद्र है — चाय बागानों, कृषि-आधारित उद्योगों और पारिस्थितिकीय व सांस्कृतिक पर्यटन के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र। नया एयरपोर्ट दक्षिण असम के साथ पड़ोसी राज्यों (मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर) की कनेक्टिविटी सुधारेगा और पूर्वोत्तर के नश्वर व बाग़वानी उत्पादों के कार्गो परिवहन को गति देगा।

भारत पोस्ट की दो योजनाएँ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाक विभाग की दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं को 16वें वित्त आयोग चक्र (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) के लिए कुल **₹2,632 करोड़** के परिव्यय के साथ जारी रखने की मंज़ूरी दी। ध्यान दें, दोनों योजनाओं का काम अलग-अलग है।

डाक संचालन योजना — ₹1,141 करोड़

यह योजना डाक और पार्सल के **संचालन व नेटवर्क** को आधुनिक बनाएगी। इसके छह घटक हैं:

- **ग्रामीण कारोबार और डाक नेटवर्क तक पहुँच (₹120 करोड़):** 33,500 ग्रामीण डाकघरों का सेवा-केंद्र के रूप में उन्नयन व मानकीकृत ब्रांडिंग।
- **मेल नेटवर्क अनुकूलन (₹575 करोड़):** 160 मेल हब, 7,000 डिलीवरी कार्यालयों और 17 मेल मोटर सेवा कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण, सड़क परिवहन नेटवर्क और 10,000 स्मार्ट 24x7 लेटर बॉक्स।
- **पार्सल नेटवर्क अनुकूलन (₹278 करोड़):** 67 पार्सल हब और 510 पार्सल पैकेजिंग यूनिट।
- **अंतर्राष्ट्रीय डाक ढाँचा (₹8 करोड़):** 5 विदेशी डाकघरों (FPO) व सब-FPO का उन्नयन।
- **विपणन एवं सेवा गुणवत्ता (₹100 करोड़):** 1 लाख डाक चौपाल सहित बहु-माध्यम अभियान।
- **फिलाटेली (डाक-टिकट संग्रह) संचालन (₹60 करोड़):** 150 प्रदर्शनियाँ, एक राष्ट्रीय फिलाटेली संग्रहालय, नई डिज़ाइन की टिकटें, 'दाई अक्षर' पत्र-लेखन प्रतियोगिता और SPARSH छात्रवृत्ति।

एस्टेट्स प्रबंधन योजना — ₹1,491 करोड़

यह योजना डाक विभाग की **भौतिक संपत्ति** यानी भवनों और आवासीय कॉलोनियों पर केंद्रित है। इसके घटक:

- **नया निर्माण (₹280 करोड़):** खाली विभागीय भूमि पर 190 नए विभागीय भवन, किराए के परिसरों का विकल्प।
- **पुनर्निर्माण (₹108 करोड़):** 50 जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण व पुनर्निर्माण।
- **नवीनीकरण व ब्रांडिंग (₹318 करोड़):** 2,550 विभागीय उप-डाकघर।
- **किराए के डाकघरों का उन्नयन (₹37.50 करोड़):** 2,500 कार्यालयों में एकरूप ब्रांडिंग।
- **धरोहर संरक्षण (₹180 करोड़):** 20 ऐतिहासिक डाक भवनों का जीर्णोद्धार।
- **कॉलोनी नवीनीकरण (₹357.50 करोड़):** 150 आवासीय कॉलोनियाँ।
- **संलग्न व समावेशी गतिविधियाँ (₹110 करोड़):** सौर ऊर्जा, वर्षा-जल संचयन, दिव्यांग-सुलभता, महिला शौचालय व शिशु-आहार कक्ष।
- **समेकित प्रौद्योगिकी केंद्र (₹100 करोड़):** बेंगलुरु में डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (CEPT) का स्थायी केंद्र।

26 नवंबर की ब्रीफिंग: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डाक सचिव सुब्रत दास ने 26 नवंबर 2026 को इन योजनाओं का विवरण दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि विभाग का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 में वार्षिक राजस्व लगभग **₹19,803 करोड़** तक ले जाना है — परिचालन दक्षता, पार्सल व लॉजिस्टिक्स विस्तार और तकनीक के उपयोग से। एकीकृत बीमा प्रबंधन प्रणाली (IMS) से अब डाक जीवन बीमा (PLI) की पॉलिसी खरीदने की पूरी प्रक्रिया लगभग 20 मिनट में पूरी हो जाती है; इससे अब तक लगभग 2 लाख ग्राहकों के लगभग ₹60 करोड़ के प्रीमियम लेनदेन हुए हैं।

नेटवर्क का पैमाना: भारतीय डाक के पास लगभग 1.65 लाख डाकघरों का नेटवर्क है, जिसका बड़ा हिस्सा (करीब 1.5 लाख) ग्रामीण क्षेत्रों में है। डाकघरों से बचत बैंक (POSB), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), PLI, आधार सेवाएँ, पासपोर्ट सेवा केंद्र और दाकघर निर्यात केंद्र जैसी सेवाएँ भी मिलती हैं।

पैसा किसका लगेगा

पाँचों फैसलों की कुल राशि ₹19,934 करोड़ है, मगर यह पूरी राशि सरकारी खज़ाने से नहीं जा रही:

- **सरकारी बजट से:** CIE योजना (₹11,000 करोड़) और डाक विभाग की दोनों योजनाएँ (₹2,632 करोड़)।
- **निजी निवेश से:** कामराजार टर्मिनल (₹4,288.26 करोड़) — कंसेशनर लगाएगा; KPL केवल ₹450 करोड़ ड्रेजिंग पर खर्च करेगा।
- **AAI के आंतरिक संसाधनों से:** सिलचर एयरपोर्ट (₹2,014 करोड़)।

महत्व और चुनौतियाँ

महत्व: कामराजार टर्मिनल पूर्वी तट पर ट्रांसशिपमेंट क्षमता बढ़ाएगा और चेन्नई-श्रीपेरंबदूर-ओरगडम, होसूर, बेंगलुरु, श्रीसिटी व तिरुपति जैसे औद्योगिक समूहों को सीधी सेवा देगा; यह मेरिटाइम इंडिया विज़न 2030 और मेरिटाइम अमृत काल विज़न 2047 के लक्ष्यों से जुड़ा है। सिलचर एयरपोर्ट बराक घाटी और पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी बदल देगा। डाक योजनाएँ ई-कॉमर्स के दौर में भारत पोस्ट को आधुनिक लॉजिस्टिक्स संगठन बनाने की दिशा में कदम हैं।

चुनौतियाँ: बंदरगाह टर्मिनल को कोलंबो व सिंगापुर जैसे स्थापित ट्रांसशिपमेंट केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी — रेल-सड़क संपर्क और प्रतिस्पर्धी टैरिफ तय करेंगे कि माल भारतीय बंदरगाह पर आए या नहीं। एयरपोर्ट की सफलता यात्री अनुमानों के सच होने और AAI के आंतरिक संसाधनों की क्षमता पर टिकी है। डाक विभाग के सामने पत्र-डाक घटने और निजी कूरियर से प्रतिस्पर्धा की चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

कामराजार टर्मिनल के लिए पारदर्शी वैश्विक बोली प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए और पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ बोली की अंतिम तिथि से पहले लेनी होंगी। सिलचर एयरपोर्ट में निर्माण की गति और बराक घाटी के अन्य ज़िलों से सड़क संपर्क पर ध्यान देना होगा। डाक विभाग को घोषित राजस्व लक्ष्य पाने के लिए पार्सल और लॉजिस्टिक्स में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए सेवा गुणवत्ता बनाए रखनी होगी। कुल मिलाकर इन फैसलों की सफलता क्रियान्वयन की गति पर निर्भर करेगी।

परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

बिंदु	तथ्य
बैठक की तिथि	25 नवंबर 2026 (केंद्रीय मंत्रिमंडल व CCEA)
कुल वित्तीय परिमाण	₹19,934 करोड़ (पाँच निर्णय)
कामराजार टर्मिनल	₹4,288.26 करोड़, PPP/DBFOT, 40 वर्ष रियायत, 2.0 मिलियन TEU
KPL का अलग व्यय	₹450 करोड़ (ड्रेजिंग)
सिलचर एयरपोर्ट	₹2,014 करोड़, AAI के आंतरिक संसाधन, डोलू (कछार, असम)
डाक संचालन योजना	₹1,141 करोड़ (2026-27 से 2030-31)
एस्टेट्स प्रबंधन योजना	₹1,491 करोड़ (2026-27 से 2030-31)
भारत पोस्ट राजस्व लक्ष्य	वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग ₹19,803 करोड़

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: 25 नवंबर 2026 की कैबिनेट मंज़ूरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: कामराजार पोर्ट का दूसरा कंटेनर टर्मिनल पूर्णतः भारत सरकार के व्यय से बनाया जाएगा।

कथन 2: सिलचर के डोलू में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का वित्तपोषण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आंतरिक संसाधनों से होगा।

कथन 3: डाक संचालन योजना के अंतर्गत फिलाटेली संचालन भी शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (b)

कथन 1 ग़लत है: टर्मिनल DBFOT आधार पर PPP मोड में बनेगा और निवेश निजी कंसेशनर करेगा; भारत सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा। KPL केवल ड्रेजिंग पर लगभग ₹450 करोड़ खर्च करेगा।

कथन 2 सही है: ₹2,014 करोड़ की परियोजना AAI अपने आंतरिक संसाधनों से पूरी तरह वित्तपोषित करेगा।

कथन 3 सही है: डाक संचालन योजना के छह घटकों में फिलाटेली संचालन (₹60 करोड़) शामिल है।

प्रश्न 2: डाक विभाग की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं:

कथन-I: एस्टेट्स प्रबंधन योजना के अंतर्गत धरोहर डाक भवनों का संरक्षण किया जाएगा।

कथन-II: डाक संचालन योजना के अंतर्गत 190 नए विभागीय भवनों का निर्माण किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए:

(a) कथन-I सही है, परन्तु कथन-II सही नहीं है

(b) कथन-I सही नहीं है, परन्तु कथन-II सही है

(c) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

(d) कथन-I और कथन-II दोनों सही नहीं हैं

▼ उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन-I सही है: एस्टेट्स प्रबंधन योजना में 20 धरोहर डाक भवनों के संरक्षण के लिए ₹180 करोड़ का प्रावधान है।

कथन-II ग़लत है: 190 नए विभागीय भवन एस्टेट्स प्रबंधन योजना (₹280 करोड़ घटक) के अंतर्गत बनेंगे, डाक संचालन योजना के अंतर्गत नहीं। संचालन योजना मेल-पार्सल नेटवर्क, मेल हब, पार्सल हब और फिलाटेली जैसे संचालन कार्यों से जुड़ी है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"भारत को अपने बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए निजी पूँजी और विशेषज्ञता की आवश्यकता है।" कामराजार पोर्ट के दूसरे कंटेनर टर्मिनल के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में:

भारतीय बंदरगाहों का बढ़ता कंटेनर ट्रैफ़िक (2019-20 में 17.2 मिलियन TEU से बढ़कर 2025-26 में 25.7 मिलियन TEU) और कामराजार पोर्ट के दूसरे टर्मिनल की PPP/DBFOT मंज़ूरी (₹4,288.26 करोड़) का संदर्भ दें।

मुख्य भाग में:

DBFOT मॉडल के लाभ (सरकारी खज़ाने पर शून्य भार, निजी पूँजी व तकनीक, उपयोगकर्ता शुल्क से वसूली), ट्रांसशिपमेंट पर विदेशी हब से निर्भरता घटना, पूर्वी तट के औद्योगिक समूहों को लाभ और रोज़गार (निर्माण में ~750, संचालन में ~800) लिखें। साथ ही जोखिम भी दें — कोलंबो/सिंगापुर से प्रतिस्पर्धा, हिंटरलैंड रेल-सड़क संपर्क और टैरिफ की प्रतिस्पर्धी क्षमता, रियायतग्राही चयन की पारदर्शिता।

निष्कर्ष में:

समयबद्ध बोली प्रक्रिया, पर्यावरणीय मंज़ूरी और मेरिटाइम अमृत काल विज़न 2047 के लक्ष्यों के साथ तालमेल पर सकारात्मक समापन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: DBFOT मॉडल क्या होता है और इसमें सरकार का पैसा क्यों नहीं लगता? उत्तर: DBFOT यानी 'डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर'। इसमें निजी कंसेशनर परियोजना को डिज़ाइन करता है, वित्त की व्यवस्था करता है, बनाता और तय अवधि तक चलाता है, फिर संपत्ति सरकार को सौंप देता है। निवेश कंसेशनर करता है और उपयोगकर्ता शुल्क से वसूलता है, इसलिए कामराजार टर्मिनल पर भारत सरकार का कोई वित्तीय भार नहीं है।

प्रश्न 2: डाक संचालन योजना और एस्टेट्स प्रबंधन योजना में क्या अंतर है? उत्तर: डाक संचालन योजना (₹1,141 करोड़) मेल-पार्सल नेटवर्क, मेल हब, पार्सल हब, अंतर्राष्ट्रीय डाक, विपणन और फिलाटेली जैसे 'संचालन' से जुड़ी है, जबकि एस्टेट्स प्रबंधन योजना (₹1,491 करोड़) डाकघरों के भवनों के निर्माण, नवीनीकरण, ब्रांडिंग, आवासीय कॉलोनियों और धरोहर भवनों जैसी 'भौतिक संपत्ति' से जुड़ी है।

प्रश्न 3: भारत पोस्ट का वित्त वर्ष 2026-27 का राजस्व लक्ष्य क्या है? उत्तर: डाक सचिव ने 26 नवंबर 2026 की ब्रीफिंग में बताया कि विभाग का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 में वार्षिक राजस्व लगभग ₹19,803 करोड़ तक पहुँचाना है — परिचालन दक्षता, पार्सल व लॉजिस्टिक्स सेवाओं के विस्तार, तकनीकी उपयोग और ग्राहक सहभागिता से।

स्रोत

1. कैबिनेट ब्रीफिंग दस्तावेज़, 25 नवंबर 2026 — PIB
2. कामराजार पोर्ट द्वितीय कंटेनर टर्मिनल की CCEA मंज़ूरी — PIB, 25 नवंबर 2026
3. डोलू (सिलचर) ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की CCEA मंज़ूरी — PIB, 25 नवंबर 2026
4. डाक संचालन योजना की मंज़ूरी (₹1,141 करोड़) — PIB, 25 नवंबर 2026
5. एस्टेट्स प्रबंधन योजना की मंज़ूरी (₹1,491 करोड़) — PIB, 25 नवंबर 2026
6. भारत पोस्ट रूपांतरण ब्रीफिंग, ₹2,632 करोड़ परिव्यय — PIB, 26 नवंबर 2026